SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: He has not said anything about the compensation paid to the workers in the Eastern Coalfields.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: Normally, Rs. 30,000 per worker is given.

MR. SPEAKER: This is not a complicated matter. You have to multiply this by the number of persons.

Question No. 534.

किसानों को डीजल की सप्लाई

*534. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिये डीजल अभी तक उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या गत तीन महीनों के दौरान राजस्थान सरकार को डीजल कम सप्लाई किया गया है और यदि हां, तो कितना डीजल कम सप्लाई किया गया है और उस के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार डीजल की उचित वितरण पद्धति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय अक्तूबर, 1979 से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल तेल का मासिक आवंटन कर रहा है। आगे और विभिन्न क्षेत्रों के बीच डीजल का आवंटन करना सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है । परन्तु उन्हें यह परामर्श दिया गया है कि वे कृषि आवश्यकताओं को उच्चतम प्राथमिकता दें। मार्च, 1980 के आरम्भ से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एच एस डी का आवंटन उदार पमाने पर किया गया है। इस को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों की ओर से कृषकों को कृषि कार्यों के लिये डीजल देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

(ख) राजस्थान के सम्बन्ध में मार्च से जून, 1980 के लिये हाई स्पीड डीजल के आवंटन और बिक्री तथा 1979 के तदनुरूपी महीनों की बिक्री सम्बन्धी ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े मी० टनों में)

हाई स्पीड डीजल आयल

माह	1980 के लिए एलोकेशन	1980 में बिक्री	1979 में बिक्री
मार्च	40000	42490	35645
अप्रैल	39000	39490	33308
मई	43132	43250 (प्रोविजनल)	39106
जून	42000	--	38342

हाई स्पीड डीजल की मार्च और मई 1980 के बीच हुए विक्रय (सप्लाई) इन महीनों के लिए किये गये आवंटन की तुलना में अधिक तथा इसी प्रकार पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों के विक्रय की तुलना में अधिक रहा है ।

(ग) राज्यों जिसमें राजस्थान भी शामिल है को राज्य के अन्दर हाई स्पीड डीजल का सही और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मार्ग निर्देशन पहले ही जारी किए गए हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : आप ने मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया है, उस को मैंने देखा है । मैं जानना चाहता था कि राजस्थान सरकार की कितनी मांग थी और आप ने उन की मांग को वीड-आउट कर के कितना परसेन्ट दिया, लेकिन आप ने जो उत्तर दिया है उस से मालूम हुआ कि मार्च महीने में आप ने उन को 40000 मीट्रिक टन एलोकेट किया, जब कि उन की सेल 42490 मीट्रिक टन की बतलाई गई है । आप ने जो तीन तरह के आंकड़े दिये हैं उन से मालूम होता है कि वहां कोटा लेने वालों की तादाद बहुत है लेकिन सप्लाई कम है । इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की कितनी मांग थी, और उस मांग का कितना परसेंट आपने राजस्थान को दिया जब कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हिन्दुस्तान में दूसरा प्रान्त है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, जहां तक स्टेट का सम्बन्ध है चूंकि डीजल की शार्टेज है इस लिये हर स्टेट ज्यादा डिमाण्ड करती है और जब ज्यादा डिमाण्ड करती है तो डिमाण्ड और कन्जम्पशन का सम्बन्ध नहीं रहता है, इस लिये यह सवाल पैदा हो जाता है कि कौन से बेसिज पर दिया जाय । हर स्टेट की एंकजाइटी होती है कि जितना ज्यादा हो सके, डीजल हासिल किया जाय । मेरे पास वहां के गवर्नर साहब का एक लैटर 21 अप्रैल, 1980 को आया था, जिस में उन्होंने कहा था कि उन की स्टेट को 53720 मीट्रिक टन का एलाटमन्ट होना चाहिय, जब कि किसी वक्त भी राजस्थान की हिस्ट्री में इतनी डिमाण्ड नहीं थी और इतनी सेल भी नहीं थी ।

श्री मूल चन्द डागा : 53720 मीट्रिक टन के लिये वहां के गवर्नर ने लिखा, जब कि उस समय वहां आप का शासन था, मैं जानना चाहता हूं कि आप ने कितने परसेन्ट कम दिया ? कई छोटे-छोटे राज्य हैं जिनको उन की मांग के हिसाब से ज्यादा मिला है, जब कि राजस्थान के बारे में मैंने तीन महीने का पूछा तो मालूम हुआ कि आप ने हर महीने 25-30 परसेन्ट कोटा कम दिया है, डिमाण्ड से कम, इस का क्या कारण है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल · मैंने अभी बतलाया कि हर स्टेट ज्यादा डिमाण्ड कर रही है और जो कन्जम्पशन है वह भी बहुत बढ़ रहा है - 1977-78 में एच० एस० डी० का कन्जम्पशन 77 लाख 40 हजार मीट्रिक टन था, 1978-79 में 86 लाख 38 हजार था, 1979-80 में 97 लाख 27 हजार हो गया । इस तरह से 1977-78 मे 8.9 परसेन्ट कन्जम्पशन बढ़ा, 1978-79 मे 11.5 परसेन्ट बढ़ा, 1979-80 में 12 6 परसेन्ट बढ़ा ।

डीजल का कन्जम्पशन हमारे देश मे बहुत बढ़ रहा है और जितना कन्जम्पशन बढ रहा है, उस को पूरा 100 परसेन्ट हम सप्लाई कर सकत है --एसी गारन्टी नही दे सकते । इसी लिये हम हर स्टट को एलोकेट कर रहे है । हर स्टट गवर्नमेंट को मालूम है कि देश में डीजल की शार्टेज है, इस लिये ज्यादा डिमाण्ड कर रहे है।

श्री मूल चन्द डागा आप ने जो माइड-लाइन्स स्टट्स को दी है, उस मे काश्तकार चाहता है.....

MR. SPEAKER: You have asked your supplementary. You should not try to monopolise this.

Mr. Ghosh.

SHRI NIREN GHOSH: Since Agriculture occupies a very important position in the country, will the hon. Minister tell us what is the normal quantity of diesel which is required for maximising the production in agriculture? What is the percentage which you have supplied during the last three years?

SHRI VEERENDRA PATIL: So far as the requirement of the agricultural sector is concerned, it has to be met by the State Governments. We don't determine them here, as to how much quantity should be allocated to the different sectors. We make bulk supply to the State Governments. The State Governments in turn allocate quantities to different sectors in the State. We have given gidelines that top priority should be given to agricultural sector. Whatever demand from the agricultural sector is there, it should be met fully.

SHRI NIREN GHOSH: My question relates to meeting the needs of the agriculturists. I asked a specific question. I wanted to know the farmers' needs and the supply which you have made during the last three years. That is what I wanted to know.

SHRI VEERENDRA PATIL: Agricultural sector includes the farmers also. I have made it already very clear that as far as the needs of the farmers are concerned, they will be fully met. These are the guidelines and directives which the Central Government has issued to the State Governments.

SHRI SUNIL MAITRA: We have heard the Minister saying about the increasing demand of diesel now. In the month of May this year for West Bengal you allowed 65,400 M.T. of High speed diesel. But in June this year, it has been reduced to 50,600 M.T. only. May I know what is the reason?

SHRI VEERENDRA PATIL: Normally the demand in the month of June will go down. While fixing the quantity we take into consideration the supply that was made during the last year. On the basis of last year's supply we have supplied more quantity in this year.

Narmada Main Canal

*537. SHRI AMARSINGH V. RATHAWA: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Narmada main canal will be one of the largest canals in India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the estimated cost of the project?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDAY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The estimated cost of the Narmada Canal System is Rs. 2639 crores, as per the latest report submitted by Government of Gujarat.